

Ques - आधुनिक काल में सार्वजनिक व्यय की वृद्धि के कारणों का उल्लेख कीजिए। क्या यह सर्वदा उचित है?

अथवा - हाल के वर्षों में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारणों का विश्लेषण करें?

अथवा - भारत में सार्वजनिक व्यय की वृद्धि के कारणों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए? (Reasons for the Growth of Public Expenditure)

Ans → सार्वजनिक व्यय सार्वजनिक क्रियाओं का आदि और अन्त है। क्लासिकल विचारकों और निर्वाणवादी विचारकों ने सार्वजनिक व्यय के विषय की अवहेलना की क्योंकि उनका ऐसा विश्वास था कि राज्य को आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार व्यक्तिवादी और आराजकवादी विचारकों ने भी राज्य हस्तक्षेप को एक आवश्यक बुराई ही समझा तथा सरकारी व्यय को "जनता के धन का अपभ्रंश" बताया। जे. बी. से (J.B. Say) के विचारानुसार "वित्त की सारी योजनाओं में सर्वोत्तम वह है जिसमें कम खर्च किया जाय"। एडम स्मिथ का मत था कि राज्य के कार्य न्याय, प्रतिरक्षा और कुछ सार्वजनिक सेवाओं के प्रबंध तक सीमित रहने चाहिए। एक अमेरिकी भाष्यकार के मतानुसार "पुराने अंग्रेज लेखकों को व्यय के सिद्धान्त की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि सरकार के सम्बंध में उनका जो सिद्धान्त था उसका तात्पर्य था सरकारी कार्यों की एक निश्चित सीमा"।

इस प्रकार प्राचीन अर्थशास्त्री राज्य के कार्यों की सीमित रखना चाहते थे क्योंकि वे सरकारी कार्यों को प्रायः अनुत्पादक तथा समाज को विशेष लाभ न देने वाले मानते थे। परन्तु आधुनिक युग में इस दृष्टि में काफी परिवर्तन आ गया है तथा सार्वजनिक व्यय का महत्व दिनोदिन बढ़ता ही जा रहा है।

20 वीं शताब्दी में बढ़ते हुए सार्वजनिक व्यय को देखकर प्रो. फ्रिडलैंड शिराज ने कहा था "संक्षेप में बीसवीं शताब्दी में सार्वजनिक व्यय में इस अंश तक वृद्धि हुई है कि कुछ ही वर्ष पहले इसे वित्तीय पागलपन का प्रतीक तथा विश्व शांति के दुर्लभ की आवश्यक निशानी समझा गया होता।" आधुनिक काल में केन्द्रिय तथा स्थानीय दोनों प्रकार के सरकारों के कार्यों में विस्तृत तथा गहन वृद्धि हुई है। वस्तुतः सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के एक नहीं बल्कि अनेक कारण हैं। प्रथम विश्व ने सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का सर्वाधिक मुख्य कारण हाल के वर्षों में आर्थिक एवं सामाजिक व्यय में वृद्धि का माना है जो दुसरी और एलेन एवं प्राउगली ने सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के लिए इन चार कारणों को मुख्य रूप से उत्तरदायी बताया है।

राज्यों की जनसंख्या एवं क्षेत्र में वृद्धि, युद्ध तथा उद्भूत तैयारी-समान्य मुद्दों तल में अतिथि वृद्धि तथा आधुनिक जटिल समाज की तेजी से बढ़ी हुई आवश्यकताएँ। किन्तु प्रोफ़ टैलर (Taylor) के अनुसार आधुनिक राज्यों के कार्यों में गहन तथा विस्तृत दोनों ही प्रकार की वृद्धि हुई है जिनके फलस्वरूप सार्वजनिक व्यय में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है सार्वजनिक व्यय में इस तीव्र वृद्धि के कारण निम्नांकित हैं।

(1) प्रतिरक्षा व्यय में वृद्धि (Increase in defence expenditure) प्रोफ़ जे.के. मेहता (J.K. Mehta) के मतानुसार अस्त्र अस्त्र पर भारी व्यय किए जाने के कारण सार्वजनिक व्यय में कई प्रतिशत वृद्धि हो गई है। अणुशक्ति के विकास, जल और वायु सेना के उपभोग, युद्ध की विशालता के कारण युद्ध का खर्चा असाधारण हो गया है। अतएव युद्ध संचालन की व्ययपूर्णता तथा युद्ध की बढ़ी हुई संभावनाओं के कारण प्रत्येक राष्ट्र की प्रतिरक्षा पर भारी मात्रा में व्यय करना पड़ रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हमारे देश में संघ सरकार की बजट का लगभग 50 प्रतिशत भाग प्रतिरक्षा पर व्यय किया जाता था

(2) आर्थिक अवसाद (Economic depression) सार्वजनिक व्यय आर्थिक मंदी को रोकने का एक प्रभावशाली अस्त्र सिद्ध हो चुका है, संयुक्त राज्य अमेरिका की New Deal Policy इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। जिसके कारण भी सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हुई है।

(3) — कीमतों के बढ़ने की प्रवृत्ति (Rising trend of prices) द्वितीय महँदुकी के बाद से लगभग प्रत्येक देश में मूल्य स्तर में वृद्धि की प्रवृत्ति रही है। मूल्य स्तर में वृद्धि होने के साथ ही सरकारें इस बात के लिए ब्राध हो जाती हैं कि वे उन वस्तुओं व सेवाओं के लिए अधिक धन का भूगतान करें जिन्हें वे चाहती हैं और सरकारी कर्मचारियों के वेतन तथा मंडँगई अने में वृद्धि करें यह स्थिति सरकारी व्यय को और विस्तार करती है।

(4) — आवश्यकताओं की सामूहिक संतुष्टि (Collective satisfaction of wants) आजकल आवश्यकताओं की सामूहिक संतुष्टि को विशेष महत्व दिया जाता है क्योंकि शक्तों इसमें मितव्ययिता होती है और दूसरे नागरिक अनेक तरह की असुविधाओं से मुक्त हो जाते हैं। यही कारण है कि आजकल बिजली आपूर्ति, जल व पूर्ति यातायात की व्यवस्था आदि ~~राज्य~~ राज्य द्वारा संचालित की जाती है जिससे सरकारी व्यय की मात्रा में वृद्धि हुई है।

(5) राज्य की कार्यक्षमता में वृद्धि (Increase in the efficiency of state)

अनेक क्षेत्रों में निजी संस्थाओं की अपेक्षा सार्वजनिक संस्थाओं की कार्यक्षमता में वृद्धि हो गई है। क्योंकि निजी संस्थाओं के सामने मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है जबकि सार्वजनिक संस्थाओं के सामने जनता का अधिक से अधिक कल्याण करना मुख्य उद्देश्य होता है।

⑥ → जनसंख्या में वृद्धि (Increase in Population) सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण जनसंख्या दर में तीव्र वृद्धि भी है। विगत वर्षों में विश्व की जनसंख्या में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विगत 45 वर्षों में विश्व की जनसंख्या 155 करोड़ से बढ़कर 415 करोड़ हो गई है। भारत की जनसंख्या 1981 के जनगणना के अनुसार 68.38 करोड़ हो गई है। भारत की अबादी में लगभग 2.5 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। सरकार को बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, आवास आदि पर काफी मात्रा में व्यय करना पड़ता है।

⑦ → जनतंत्रीय शासन पद्धति का विकास (Growth of the Democratic form of Government) — जनतंत्रीय शासन पद्धति के प्रादुर्भाव के कारण भी सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हुई है। इसकी इस शासन प्रणाली में विधान मण्डल आदि पर बड़ी मात्रा में व्यय होता है और दूसरे जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए सरकार होने के नाते सरकार को जनहित के लिए सभी कार्य करने पड़ते हैं। जनतंत्रीय शासन में सतारूढ़ दल को अपने पक्ष में करने हेतु जनता की सभी सुख सुविधाएँ जुटानी पड़ती हैं और कभी कभी विरोधी राजनीति दलों का मुँह बन्द करने हेतु अनावश्यक व्यय भी करना पड़ता है।

⑧ — राष्ट्रीय आय में वृद्धि (Increase in National Income) विगत वर्षों में पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के कारण लगभग सभी देशों की राष्ट्रीय आय और संपन्नता बढ़ी है। फलतः एक ओर सरकार जनता से प्रचुर मात्रा में आय प्राप्त करने में समर्थ हो गयी है तथा जनता भी सरकार से अपने लिए अधिक सुख सुविधाओं की माँग करने लगी है। अतएव इन दोनों कारणों से सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हुई है।

⑨ कल्याणकारी राज्य की भावना का विकास (Growth of the spirit of welfare-state) आजकल राज्य को ही सर्वोत्तम समझा जाता है तथा यह विश्वास किया जाता है कि राज्य के उपर अपने नागरिकों के जीवन संचालन और विकास का पूरा उत्तरदायित्व है। आजकल प्रत्येक देश की सरकार के सामने कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य है तथा कल्याणकारी क्रियाओं के रूप में सरकार ने बेकारी बीमा, स्वास्थ्य बीमा, इहावस्था पेंशन, प्रसव लाभ, बीमारी बीमा, निःशुल्क शिक्षा और चिकित्सा आदि का दायित्व अपने उपर ले लिया है। इन सब कार्यों को सम्पन्न करने के लिए सार्वजनिक

सार्वजनिक ऋण में हद तक बढ़ाई है।

(10) - उद्योगों का समाजीकरण (Socialization of Industries) :- समाजवादी प्रकृति के प्रसार के फलस्वरूप आजकल सार्वजनिक उपक्रम का क्षेत्र व्यापक होता जा रहा है। प्रमुख पूंजीवादी देशों में भी उनके आवश्यक एवं सुरक्षा संबंधी उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्य सरकार द्वारा होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हमारे देश में उद्योगों की स्थापना की गई है जिसके कारण भी सार्वजनिक ऋण के अंकड़ में हद तक बढ़ाई है।

(11) आर्थिक नियोजन (Economic Planning) समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं में नियोजन एक प्रमुख लक्ष्य होता है, मिश्रित देश में भी देश के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य से आर्थिक नियोजन की नीति अपनाई जाती है। आर्थिक नियोजन की केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यक्रमों और विकास परियोजनाओं को पूरा करने हेतु अपार धन की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति के लिए सरकार को हर संभव साधनों का सहारा लेना पड़ता है। जिससे सार्वजनिक ऋण में बहुत अधिक हद तक बढ़ाई जाती है।

(12) - ऋण तथा ऋण की अदायगी (Debt Servicing) :- कार्यमूलक वित्त व्यवस्था के अंतर्गत घाटे के बजट को समान्य स्वीकृति प्रदान की जाती है राज्य अपनी आय से अधिक ऋण करता है और इसके लिए देश के आंतरिक अथवा वाह्य स्रोतों से ऋण लेता है। अब ऋण पर देय भुगतान एवं मूलधन की वापसी पर भी राज्य की आय का एक बड़ा भाग व्यय किया जाता है।

(13) प्रतिरक्षा की समस्या (Problem of Defence) - इसमें कोई दो मत नहीं है कि देश की प्रतिरक्षा की समस्या सरकारी खर्च में हद तक एक प्रमुख कारण बन गई है। कोई देश अपनी प्रतिरक्षा के लिए सेनाओं को अकिंभाली बनाना चाहता है तो दुखरे केवल आत्मरक्षा के लिए ऐसा कदम उठाने को विवश हो जाता है। कुछ संबंधी हथियारों का निर्माण तथा सेना के रख रखाव पर भारी धनराशि व्यय करनी पड़ी है। फिर कुछ लड़ने की विधिओं में दिनरात जो परिवर्तन होते रहते हैं उसके कारण भी सेना को नये नये हथियारों की आवश्यकता होती है। इससे राज्य पर खर्च का भार बढ़ता है। प्रतिरक्षा व्यय में केवल सैनिक एवं सैनिक सामग्री का व्यय ही सम्मिलित नहीं होता है बल्कि सैनिकों की पेन्शन तथा भुक्तान हेतु लिए गये ऋण पर भी व्यय भी शामिल होता है। कुछ के विज्ञान और कला में इतनी अधिक प्रगति हुई है कि आज के अस्त काल अप्रचलित एवं पुराने हो जाते हैं जिससे कुछ समस्याएँ बड़ी खचीली हो जाती हैं। अमेरिका में कुल वार्षिक बजट का 30% भाग प्रतिरक्षा पर व्यय किया जाता है। भारत में कुल राष्ट्रीय आय का 3.5% पाकिस्तान में 4% तथा दक्षिण कोरिया में 6% राशि प्रतिरक्षा पर व्यय की जाती है।

(14) उत्पादक का सरकारी सहायता :- आजकल प्रत्येक देश की सरकार अर्थव्यवस्था को आत्म निर्भर बनाने के लिये से उत्पादन को बढ़ाने और प्रोत्साहित करने हेतु छोटे छोटे उत्पादकों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है तथा उनके लिये ऋण की भी व्यवस्था करती है। राज्य सरकार की इस प्रवृत्ति के कारण ही सार्वजनिक ऋण में वृद्धि हुई है।

(15) :- नागरिक प्रशासन (Civil Administration) जनसेवका की तीव्र गति से वृद्धि आहरीकरण और समाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों के विकास के कारण राज्य का कार्य बहुत बड़ा गया है। राज्यों के कार्यों में गहनता एवं विस्तार के साथ ही साथ राज्य के प्रशासनिक ढांचे में तथा सरकार द्वारा गरिब निकाश, नियंत्रण व्यवस्था, सामान्य सेवाओं आदि के क्षेत्र में विस्तार हुआ है और राजस्व कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि भी हुई है जिससे उनके वेतन भत्ते आदि पर व्यय में वृद्धि स्वाभाविक है। भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या में पिछले 40 वर्षों में 17 गुणा और उनके वेतन आदि मद में 58 गुणा वृद्धि हुई है।

(16) कृषि विकास (Development of Agriculture) :- भारत जैसे विकासशील देश की अर्थव्यवस्था का कृषि विकास उसकी अर्थव्यवस्था की द्युरी है। आर्थिक विकास के लिये कृषि तथा गैर कृषि दोनों क्षेत्रों के विकास के लिये सुविधाएँ प्रदान करना आवश्यक होती है क्योंकि दोनों क्षेत्र परस्पर निर्भर करते हैं। भारत जैसे देश में आर्थिक एवं सामाजिक विकास को द्युरगति प्रदान करने के लिये कृषि ढांचे को मजबूत करना जरूरी है। इसलिये कि विकासशील देश अपने कृषि विकास के लिये बड़ी मात्रा में राशि व्यय कर रहे हैं। इसलिये सरकार किसानों को कम ऋणदर पर ऋण प्रदान करना, निर्मातों को अनुदान, कृषिगत वस्तुओं का निर्धारित मूल्य पर क्रय गठकर सुविधा प्रदान करना इत्यादि सुविधाओं पर व्यय करती है। इसके अतिरिक्त सरकार कृषि अनुसंधान एवं कृषिगत साधनों के निर्माण पर काफी मात्रा में व्यय करती है।

(17) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग (International cooperation) :- अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के अन्तर्गत प्रत्येक सरकार किसी न किसी देश को ऋण अनुदान एवं अन्य आर्थिक सहायता देती है। इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएँ जैसे I.M.F, E.B.R.D, UNICEF आदि संस्थाओं को भी समर्थन समर्थन पर सहस्रताएं शुल्क देना पड़ता है। अतः अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बनाए रखने के लिये सरकार को अधिक व्यय करना पड़ता है।

सार्वजनिक व्यय की हद पर नियंत्रण नहीं रखने पर कई तरह के बुरे परिणाम सामने आ जाते हैं। भारत में सार्वजनिक व्यय की हद के परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हुई है। कालावजारी बढी है तथा कालाधन से प्रोत्साहन मिला है। भारत सरकार को अपने व्यय के बढ़ने के कारण ही व्यापक वित्त समस्या तथा विदेशी ऋण पर निर्भर करना पड़ा है। उस इस बात का है कि भारत ऋण फन्दा (Debt Trap) में न फँस जाये। इसलिए सार्वजनिक व्यय की हद को सर्वथा उचित नहीं माना जा सकता है। वस्तुतः सार्वजनिक व्यय में तभी तक हद करनी चाहिए जब तक कि इससे अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति होती है।

समाप्त

M. Ram  
Assistant Professor  
R. B. G. College  
Maharajgarh